



16 March, 2024

## केंद्र सरकार ने ई-वाहन नीति को अपनी स्वीकृति दे दी है

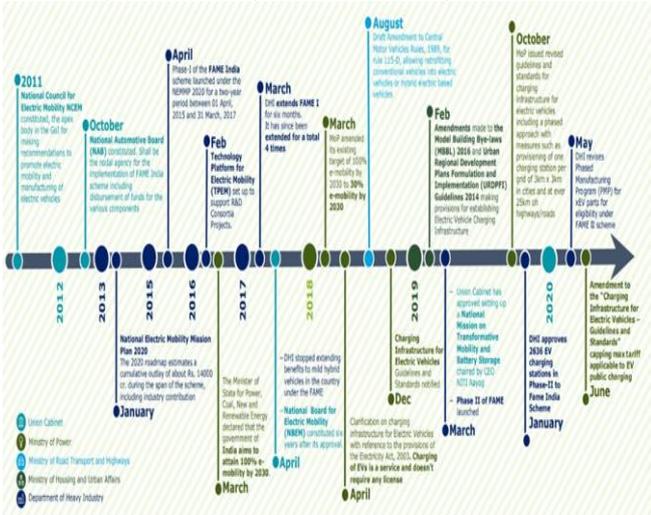
**संदर्भ:** केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक योजना, ई-वाहन नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।

### उद्देश्य:

- वैश्विक निर्माताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय उपभोक्ताओं को अत्याधुनिक तकनीक तक सुगम पहुंच प्रदान करना।
- मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करना।
- उत्पादन मात्रा बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के लिए ईवी निर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना।
- बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना।

### ई-वाहन नीति की मुख्य बातें (पॉलिसी विवरण):

- **न्यूनतम आवश्यक निवेश:** 4150 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।
- निवेश पर कोई अधिकतम सीमा नहीं।
- **विनिर्माण समय-सीमा:** 3 वर्ष के भीतर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कर, ईवी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना और 5 वर्ष के भीतर 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना।
- **घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) लक्ष्य:** विनिर्माण के तीसरे वर्ष तक 25% स्थानीयकरण और पांचवें वर्ष तक 50% स्थानीयकरण प्राप्त करना।
- **सीमा शुल्क:** 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य वाले वाहनों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 15% सीमा शुल्क लागू है, जो 3 वर्ष के भीतर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने पर निर्भर करेगा।
- **शुल्क रियायत की सीमा:** किए गए निवेश पर अधिकतम सीमा या ₹6484 करोड़ (पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन के बराबर), जो भी कम हो। यदि निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है तो प्रति वर्ष 8,000 से अधिक की दर पर 40,000 ईवी का अधिकतम आयात होनी चाहिए तभी सीमा शुल्क से रियायत मिल सकती है अन्यथा नहीं।
- **वैक गारंटी:** यह निवेश प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिसे डीवीए और न्यूनतम निवेश मानदंड पूरा न करने की स्थिति में लागू किया जाता है।



### भारत में ई-वाहनों को बढ़ावा देने की पहल:

- **FAME I और II:** यह पहल ईवी खरीद और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

- **एनईएमपी:** इसके माध्यम से वर्ष 2030 तक भारतीय सड़कों पर 30% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **कर लाभ:** ईवी ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती का प्रस्ताव किया गया है।
- **पीएलआई योजना:** इसके माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है।
- **एनटीईएम:** ईवी उद्योग सहित तकनीकी वक्कों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन आरम्भ किया गया है।
- **बैटरी विनिर्माण इकाइयां:** ईवी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है।
- **सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा:** इलेक्ट्रिक बस खरीद (उदाहरण के लिए, दिल्ली में ई-बसें) के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जा रहा है।
- **अंतिम-छोर कनेक्टिविटी:** लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बेड़े की तैनाती (उदाहरण के लिए, चेन्नई का 5,000 से अधिक वाहनों का बेड़ा) की जा रही है।
- **सरकारी सेवाओं में ई-वाहन:** सरकारी वाहनों का ईवी से प्रतिस्थापन जिया जा रहा है।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएएमपी):** यह कार्यक्रम स्वदेशी ईवी विनिर्माण और उसके घटकों की असेंबली प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।
- **परिवर्तनकारी गतिशीलता और भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन:** यह मिशन ईवी घटकों के निर्माण के लिए परिवर्तनकारी रणनीतियाँ चलाता है।

## सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024

**संदर्भ:** सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।

- भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 1983 के नियमों को प्रतिस्थापित कर सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 लाया है।

### पृष्ठभूमि:

- भारतीय फिल्म उद्योग विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उद्योग है, जो 40 से अधिक भाषाओं में वार्षिक रूप से 3,000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करता है।
- माननीय प्रधान मंत्री भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का लाभ उठाते हुए एक कंटेंट हब के रूप में परिभाषित करते हैं।
- सूचना और प्रसारण मंत्री विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में भारतीय सिनेमा की भूमिका को स्वीकार करते हैं।

### सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024:

- इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल युग के लिए फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, साथ ही पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है।
- इस संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ समावेशिता और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श भी किया गया।

### प्रमुख सुधार:

- **ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाना:**
  - फिल्म उद्योग में पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए ये नियम ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं।
  - ऑनलाइन प्रक्रियाओं में यह बदलाव आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित है और फिल्म निर्माताओं के लिए एक सहज प्रमाणन अनुभव की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रसंस्करण समयसीमा में कमी:**
  - एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में फिल्म प्रमाणन के प्रसंस्करण हेतु समयसीमा को कम करना शामिल है।





16 March, 2024

- प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने से, प्रमाणन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी समाप्त हो जाती है, जिससे फिल्म निर्माताओं के लिए त्वरित बदलाव सुनिश्चित होता है।
- आयु-आधारित प्रमाणीकरण श्रेणियों का परिचय:**
  - आयु-उपयुक्त सामग्री उपभोग सुनिश्चित करने के लिए नियम प्रमाणन की आयु-आधारित श्रेणियां पेश करते हैं।
  - मौजूदा UA श्रेणी के बजाय, फिल्मों को अब आयु समूहों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें सात वर्ष (यूए 7+), तेरह वर्ष (यूए 13+), और सोलह वर्ष (यूए 16+) शामिल हैं।
  - इन आयु वर्गीकरण का उद्देश्य बच्चों के लिए फिल्मों की उपयुक्तता का आकलन करने, उपयुक्त फिल्म देखने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए माता-पिता या अभिभावकों के लिए सिफारिशें करना है।
- सीबीएफसी में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व:**
  - नए नियम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और उसके सलाहकार पैनल में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करके लैंगिक विविधता की समाप्ति को प्राथमिकता देते हैं।
  - नए नियम में विशेष रूप से, बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है।
  - इसका उद्देश्य प्रमाणन प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करना और निर्णय लेने की भूमिकाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
- फिल्मों की प्राथमिकता स्क्रीनिंग के लिए प्रणाली:**
  - फिल्म निर्माताओं की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए एक प्राथमिक प्रणाली स्थापित की गई है।
  - यह प्रावधान उन मामलों में प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति देता है जहां फिल्म निर्माताओं के पास अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए पूर्व प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं, जिससे व्यापार संचालन में आसानी होती है।
- प्रमाणपत्रों की स्थायी वैधता:**
  - यह नया नियम सीबीएफसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की वैधता पर लगे प्रतिबंध को हटाते हैं, जिससे स्थायी वैधता सुनिश्चित होती है।
  - यह परिवर्तन फिल्म निर्माताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करता है और बार-बार प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो अधिक कुशल और स्थायी प्रक्रिया में योगदान देता है।
- टेलीविजन प्रसारण के लिए संपादित फिल्मों का पुनःप्रमाणीकरण:**
  - टेलीविजन प्रसारण के लिए संपादित फिल्मों को प्रसारण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
  - केवल अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में वर्गीकृत फिल्मों ही टेलीविजन प्रसारण के लिए पात्र होंगी, जिससे टेलीविजन दर्शकों के लिए सामग्री उपयुक्तता सुनिश्चित होगी।
- प्रगति की स्वीकृति:**
  - नए नियम पिछले 40 वर्षों में फिल्म प्रौद्योगिकी, दर्शकों की जनसांख्यिकी और सामग्री वितरण विधियों में प्रगति को स्वीकार करते हैं।
  - इस प्रकार इस नई और संशोधित फिल्म नीति का समग्र उद्देश्य फिल्म उद्योग की उभरती जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना है।

## वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल

**संदर्भ:** मध्य भारत में भारत के वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण (एआरटी-सीआई) स्थल का उद्घाटन चरण मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 50 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित सीहोर जिले के सिलखेड़ा में आरम्भ हुआ।

### ➤ एआरटी-सीआई का परिचय:

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा वित्त पोषित, एआरटी-सीआई में 25 उच्च-स्तरीय मौसम संबंधी उपकरण हैं।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य मध्य भारत के मानसून कोर जोन (एमसीजेड) पर मानसून से जुड़ी महत्वपूर्ण बादल प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है।

### ➤ एआरटी का उद्देश्य:

- एआरटी एक खुले क्षेत्र के अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान मौसम मापदंडों और सिनोप्टिक प्रणालियों का अवलोकन करना है।
- यह मौजूदा मौसम मॉडल को बेहतर बनाने और वर्षा की भविष्यवाणियों को सटीकता प्रदान करने के लिए समय के साथ उच्च मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है।

### ➤ सेटअप और संचालन:

- 100 एकड़ में फैला, एआरटी 125 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे द्वारा संचालित है।
- अपने पहले चरण में 25 मौसम संबंधी उपकरणों का उपयोग करके यह रिमोट सेंसिंग-आधारित, इन-सीटू मापन प्रक्रिया को शामिल करता है।

### ➤ एआरटी का महत्व:

- भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है, खासकर मानसून कोर जोन (एमसीजेड) वाले इलाके में।
- मध्य भारत में एआरटी का स्थान वर्षा-वाहक सिनोप्टिक प्रणालियों की सीधी निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जो मानसून के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है।

### ➤ मध्य भारत का महत्व:

- विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों ने ART के महत्व पर बल देते हुए अखिल भारतीय वर्षा प्रदर्शन को मध्य भारत में हुई वर्षा से सहसंबद्ध किया है।
- सिनोप्टिक प्रणालियों की सीमित समझ और मानसून वर्षा को बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए इस क्षेत्र में एक केंद्रित अनुसंधान की आवश्यकता है।

### ➤ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- यह अनुसंधान संस्थान जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव जोखिमों को कम करने के लिए सटीक पूर्वानुमान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- एआरटी पूर्वानुमान सटीकता को बढ़ाने के लिए क्लाउड माइक्रोफिजिक्स, वर्षा और भूमि-सतह गुणों पर दीर्घकालिक अवलोकन को सक्षम बनाता है।

### ➤ मध्य प्रदेश की भूमिका:

- सिलखेड़ा की रणनीतिक स्थिति प्रमुख वर्षा-असर वाले सिनोप्टिक प्रणाली के साथ संरेखित है, जिससे सीधी निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।
- इसके साथ ही प्रदूषकों से मुक्त प्राचीन वातावरण इसे संवेदनशील मौसम संबंधी उपकरणों को तैनात करने के लिए एक आदर्श स्थल बनाता है।

### ➤ एआरटी उपकरण:

- 100 एकड़ में फैला, एआरटी 125 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे द्वारा संचालित है।
- यह परीक्षण स्थल एथलोमीटर सहित, क्लाउड संघनन नाभिक काउंटर और रडार सहित दो दर्जन से अधिक उच्च-स्तरीय उपकरणों से सुसज्जित है।
- इसके अलावा एआरटी में 72 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान टावर है, जो वायुमंडलीय मापदंडों के निरंतर अवलोकन की सुविधा प्रदान करता है।

## Face to Face Centres





## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### कोचरब आश्रम



हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती में महात्मा गांधी आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया।

**कोचरब आश्रम के बारे में:**

- कोचरब आश्रम, गुजरात के कोचरब गांव में स्थित एक औपनिवेशिक शैली की सफेद रंग की इमारत है।
- शुरुआत में इसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन को दर्शाता है।
- यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी पर महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था।
- यह आश्रम विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन के प्रयोगों का केंद्र था।
- एक साथी वकील और सहयोगी, जीवनलाल देसाई ने गांधीजी को कोचरब आश्रम स्थापित करने में सहायता की।
- यह सत्य, अहिंसा और सादगी के गांधी के सिद्धांतों का प्रतीक है जो आज भी विश्व स्तर पर लोगों को प्रेरित करता है।

### निजी प्लेसमेंट



हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने निजी प्लेसमेंट मार्ग के माध्यम से प्रतिभूतियों के आवंटन से संबंधित कुछ परिपत्रों को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

**निजी नियोजन (Private Placement) के बारे में:**

- निजी प्लेसमेंट एक कंपनी द्वारा सार्वजनिक पेशकश किए बिना निवेशकों के एक चुनिंदा समूह को प्रतिभूतियां जारी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- यह प्लेसमेंट 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है।
- 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत निजी प्लेसमेंट की सीमा 49 लोगों को प्रतिभूति जारी करने की थी।
- इसे 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत 200 निवेशकों तक बढ़ा दिया गया था।
- इसका इस्तेमाल प्रायः पर कंपनियों द्वारा विस्तार, ऋण चुकोती या कार्यशील पूंजी जरूरतों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है।
- निजी प्लेसमेंट में शामिल कंपनियों को पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।
- निजी प्लेसमेंट को नियंत्रित करने वाले विनियमों का पालन न करने पर सेबी या अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाया जा सकता है।
- कुछ मामलों में, सेबी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, निर्धारित निवेशकों की सीमा से अधिक प्रतिभूतियां जारी करने वाली कंपनियों के लिए रियायत प्रदान कर सकता है, जैसे कि निवेशकों को वापसी या उच्च रिटर्न के विकल्प प्रदान करना।

### न्यूरोलॉजिकल विकार



हाल ही में, लैंसेट न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि 2021 में, दुनिया भर में 3.40 बिलियन व्यक्ति (43.1% वैश्विक आबादी) किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल विकार के साथ रहे थे, जिसके कारण 11.1 मिलियन मौतें हुईं।

**न्यूरोलॉजिकल विकार के बारे में:**

- न्यूरोलॉजिकल विकार वैश्विक आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करता है, दुनिया भर में अरबों व्यक्ति इस स्थिति के साथ रहते हैं।
- यह विकार विश्व स्तर पर होने वाली मौतों की संख्या में एक बड़ा योगदान देता है।
- यह विकार दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण है जो किसी व्यक्ति के उत्पादक और सार्थक जीवन जीने की क्षमता को प्रभावित करता है।
- विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) का उपयोग आमतौर पर न्यूरोलॉजिकल विकार के बोझ को मापने के लिए किया जाता है जो बीमारी, विकलांगता या अकाल मृत्यु के कारण खोए गए स्वस्थ जीवन के वर्षों को दर्शाता है।
- इसमें स्ट्रोक, अल्जाइमर रोग, मिर्गी, माइग्रेन, न्यूरोपैथी, मेनिन्जाइटिस और तंत्रिका तंत्र के कैंसर सहित कई स्थितियां शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर DALYs के प्रमुख कारणों में से एक न्यूरोलॉजिकल विकार शामिल है, जो जनसंख्या स्वास्थ्य पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है।
- हालांकि समय के साथ न्यूरोलॉजिकल विकार की व्यापकता अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है, चिकित्सा देखभाल और हस्तक्षेप में सुधार के कारण कुछ मामलों में मृत्यु दर और DALYs में कमी आई है।
- सीमित विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देश (LMIC) अक्सर न्यूरोलॉजिकल विकार का असमान बोझ उठाते हैं।
- कुछ न्यूरोलॉजिकल विकार लिंगगत असमानता दर्शाते हैं जिनमें विभिन्न आयु समूहों में व्यापकता और प्रभाव में भिन्नता होती है।

### सुर्खियों में व्यक्तित्व

#### लक्ष्मीनारायण रामदास



**लक्ष्मीनारायण रामदास (5 सितंबर 1933-15 मार्च 2024)**

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास का जन्म माटुंगा, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था।

**योगदान:**

- नौसेनाध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान (13वें) एडमिरल रामदास ने भारतीय नौसेना में महिलाओं को शामिल करने की ऐतिहासिक पहल की।
- उन्होंने आईएनएस बीएस के कमांडर के रूप में कार्य किया जो जहाज पूर्वी पाकिस्तान की नाकेबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
- उन्होंने 1973 से 1976 तक बॉन, पश्चिम जर्मनी में भारतीय नौसेना अताशी के रूप में भी कार्य किया।

**पुरस्कार और सम्मान:**

- 1971 के युद्ध के दौरान आईएनएस बीएस के कमांडर के रूप में उनकी वीरता के लिए रामदास को वीर चक्र (देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।
- दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच शांति का समर्थन करने के लिए उन्हें 2004 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

**नैतिक मूल्य:** सत्यनिष्ठा, साहस, करुणा आदि।

## Face to Face Centres





16 March, 2024

## सुर्खियों में स्थल

### डेरीएन गैप

हाल ही में, अमेरिका में अवैध आत्रजन से संबंधित चर्चाओं में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है, जिसमें दक्षिण में स्थित डेरीएन गैप पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

**डेरीएन गैप (The Darien Gap) के बारे में:**

- डेरीएन गैप उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के बीच स्थित है।
- यह क्षेत्र घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और तेज धारा वाली नदियों से युक्त है।
- इसमें पक्की सड़कें और अन्य आधुनिक बुनियादी ढांचे का अभाव है।
- यह मध्य और दक्षिण अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है।
- घनी वनस्पति और चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण, डेरीएन गैप के रास्ते यात्रा करना बेहद मुश्किल है।
- इसमें कीचड़ भरे रास्तों, खड़ी चट्टानों और अशांत नदियों को पार करने की आवश्यकता होती है।
- अपनी चुनौतियों के बावजूद, डेरीएन गैप वैश्विक मानव प्रवास के लिए एक प्रमुख मार्ग बन गया है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण मांगने वाले व्यक्तियों के लिए।
- प्रवासी प्रायः जंगल के रास्ते जाने के लिए गाइडों पर भरोसा करते हैं।
- यह क्षेत्र मानव तस्करी और तस्करी में शामिल आपराधिक संगठनों द्वारा नियंत्रित होने के लिए जाना जाता है।



## POINTS TO PONDER

- हाल ही में अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? – **ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू**
- कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और अधिकारियों की सुविधा के लिए जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? – **महाराष्ट्र**
- हाल ही में वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? – **ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा**
- मोहम्मद शतायेह के इस्तीफे के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने किसे प्रधान मंत्री नियुक्त किया है? – **मोहम्मद मुस्तफा**
- जापान ने हाल ही में किन दो देशों के साथ अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के सह-विकास के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? – **ब्रिटेन और इटली**

## Face to Face Centres

